दैनिक जागरण
साहित्य विचार एवं भाषा की साझा अभिव्यक्ति है

सबक सीखने का समय

श्रीलंका में हुए भीषण आतंकी हमलों में स्थानीय आतंकियों की लिप्तता के सुबूत सामने आने के साथ ही यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें दुनिया के सबसे बर्बर आतंकी संगठन आइएस की भी मदद मिली। अगर यह साबित हो जाता है कि श्रीलंका को आइएस की साजिश के तहत ही लहूलुहान किया गया तो इसका मतलब होगा कि सीरिया और इराक में इस आतंकी संगठन को खत्म करने के दावे निरर्थक हैं। श्रीलंका में किए गए आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या 350 से अधिक पहुंच गई है। हाल के समय में इतने अधिक लोग किसी आतंकी हमले का शिकार नहीं बने। यह एक तरह से इस दशक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। श्रीलंका आतंकियों के भयावह हमलों और उनके कारण हुई व्यापक जनहानि से बच सकता था, यदि उसके अधिकारियों ने भारत की ओर से मुहैया कराई गई खुफिया सूचना पर तनिक भी गंभीरता का परिचय दिया होता। यह हैरानी की बात है कि श्रीलंकाई अधिकारियों ने इस सटीक सूचना पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी कि आतंकी भारतीय उच्चायोग के साथ चर्चों को खास तौर पर निशाना बना सकते हैं। अब श्रीलंका में इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता हुआ दिख रहा है कि आतंकी हमलों संबंधी खुफिया सूचना की अनदेखी कैसे हुई, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जरूरी यह है कि खुफिया सूचना की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई उन पर भी की जानी चाहिए जिन्होंने आत्मघाती हमलावरों में शामिल उन तत्वों को छोड़ दिया था जो कुछ समय पहले विस्फोटक रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे।

यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि श्रीलंका के साथ-साथ शेष दुनिया भी कुछ सबक सीखे। सबसे पहला सबक तो यही है कि खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी अनदेखी न होने पाए। इसके अलावा आइएस जैसे मानवता के दुश्मन बन गए आतंकी संगठनों पर नए सिरे से लगाम लगाने के उपाय किए जाएं। पता नहीं ऐसा हो सकेगा या नहीं, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकी संगठनों को पालने-पोसने अथवा अतिवादी तत्वों की अनदेखी करने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य से ऐसे देश दक्षिण एशिया में ही हैं। ऐसे में भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि श्रीलंका में आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार माने जा रहे संगठन के तार तमिलनाडु के एक समूह से जुड़े होने का अंदेशा है। निःसंदेह बीते कुछ समय में आतंकी संगठनों पर निगाह रखने वाला तंत्र पहले की तुलना में सक्षम हुआ है और इसका एक प्रमाण यह है कि हमारे खुफिया अधिकारियों को इसकी भनक पहले ही लग गई थी कि आतंकी श्रीलंका में कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। इसके बावजूद इस तथ्य को ओझल नहीं कर सकते कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले को रोका नहीं जा सका। सक्षम और कारगर खुफिया तंत्र के निर्माण के लिए सबसे जरूरी यह है कि इस तंत्र में किसी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी न होने दी जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा को दलगत राजनीति का विषय न बनाया जाए।

चुनावी हिंसा

चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल में पहले दो चरणों में किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन तीसरे चरण में मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बालीग्राम में बूथ के बाहर दो गुटों की झड़प में धारदार हथियार से हमला कर तियारूल शेख नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात रहे मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार को जैसे ही मतदान शुरू हुआ। इसके बाद बमबाजी से लेकर गोलीबारी एवं हमले की घटनाएं शुरू हो गई थीं। परंतु इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बिना खून बहे बंगाल में मतदान क्यों नहीं संपन्न हो पा रहा है? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इस हत्या के लिए कांग्रेस ने तृणमूल को दोषी बताया है तो तृणमूल नेता आरोप को खारिज कर रहे हैं। बंगाल के विशेष चुनाव पर्यवेक्षक अजय वी नायक ने ऐसे ही नहीं प्रतिक्रिया दी कि 10-15 वर्ष पहले बिहार में जो स्थिति थी वह हाल अभी बंगाल में है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर उनके दलों के नेताओं ने जमकर नायक पर हमला किया। यहां तक आरोप लगाया गया कि भाजपा आयोग की मदद से बंगाल में समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। यदि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक होती तो क्या मतदान के दौरान किसी की जान जाती? क्या मतदान के दौरान बमबाजी एवं गोलीबारी होती? क्या बम एवं हथियार मतदान से पूर्व बरामद होते। बिहार एवं उत्तर प्रदेश में भी सात चरणों में मतदान हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में चुनावी हिंसा हो रही है वैसा तो अन्य राज्यों नहीं हो रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है। चुनाव में जीत-हार होती ही है, लेकिन खून-खराबा क्यों? मंगलवार को एडीजी (कानून-व्यवस्था) सिद्धिनाथ गुप्ता ने भी स्वीकारा कि मुर्शिदाबाद में चुनावी हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई है। शेख भगवानगोला थाने के बलीग्राम प्राथमिक स्कूल में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यही नहीं मुर्शिदाबादा एवं जंगीपुर के अलावा मालदा उत्तर, दक्षिण में भी बमबाजी एवं गोलीबारी हुई है।

चीन की चुनौती का जवाब देता भारत

हर्ष वी पंत

कई देशों में चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआइ परियोजना को लेकर संदेह पैदा हो रहे हैं। ऐसे में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की सुविधा के मोर्चे पर नए अवसर बन सकते हैं जिन्हें भुनाने की कोशिश भारत को करनी चाहिए

भारत ने जब भी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोट इनिशिएटिव यानी बीआरआइ पर कोई रुख अख्तियार किया है तो ऐसा करके उसने उसे और साथ ही दुनिया को कई संदेश देने का काम किया है। चीन एक बार फिर बीआरआइ से जुड़ा आधिकारिक आयोजन करने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए उसने भारत को भी निमंत्रण दिया था। पहले की तरह इस बार भी भारत ने इस न्यौते को ठुकरा दिया। इससे पहले भी भारत ने चीन के इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। नई दिल्ली ने मई 2017 में प्रथम बेल्ट एंड रोड फोरम (बीआरएफ) सम्मेलन का भी बहिष्कार किया था जिसमें 129 देशों और कई राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। भले ही अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने उसमें भाग लिया हो, लेकिन भारत इसे लेकर अपने रुख पर मजबूती से टिका हुआ है। वह इस चीनी पहल पर अपनी आपत्तियों को जाहिर करता रहा है। बीआरआइ के माध्यम से खुद को वैश्विक शक्ति के तौर पर पेश करने की चीनी आकांक्षाओं के लिए भारत का यह रुख एक बड़ा झटका था। भारत के इन्कार के बाद से चीन को ऐसे कई झटके लगे हैं जिन्होंने उसके लिए समस्याएं कई गुना बढ़ा दी हैं। चूंकि भारत ने एक बार फिर अपना विरोध जताया है तो बीजिंग भी इस पर अपने पत्ते फेंटेगा। इसके संकेत भी मिल गए हैं। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसका उल्लेख कुछ इस तरह किया है, 'अगर भारत बीआरआइ के तहत सहयोग से मुंह फेरता है या फिर कुछ परियोजनाओं में हस्तक्षेप करता है तो वह कई बड़ी विकास परियोजनाओं से जुड़ने का अवसर खो बैठेगा। साथ ही कई दक्षिण एशियाई देशों के साथ बेहतर जुड़ाव की उसकी योजनाओं को भी नुकसान होगा।'

नई दिल्ली का हालिया निर्णय चीन के उस रुख के बाद सामने आया है जिसमें चीन मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने की भारत की कोशिशों को लगातार झटका देता आया है। हाल के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी चीन का रुख इस मसले पर बदला नहीं। अगर वुहान वार्ता को छोड़ दिया जाए तो भारत-चीन रिश्तों के मोर्चे पर कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है। कुछ हालिया रपटों में यह सामने आया है कि डोकलाम पठार पर चीन अपनी स्थिति लगातार मजबूत बना रहा है। यह सीमा पर चुनौती को दर्शाता है। जो भी हो, भारत की संप्रभुता का मूल प्रश्न बीआरआइ को लगातार परेशान करता रहेगा। जैसा कि चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने दोहराया, 'कोई भी देश ऐसी परियोजना से नहीं जुड़ सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसकी मुख्य चिंताओं की अनदेखी करती हो।'

हालांकि बीआरआइ को लेकर बाकी दुनिया को लुभाने की चीनी मुहिम लगातार जारी है, लेकिन भारत अपने रवैये पर कायम है और उसे कायम रहना भी चाहिए। बीआरआइ से जुड़े कार्यक्रम में करीब सौ से अधिक देश हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में लगभग 40 देशों के राष्ट्रप्रमुखों के भी शामिल होने की उम्मीद है। पश्चिमी देशों में बीआरआइ को लेकर कुछ संशय और संदेह के बावजूद अभी हाल में इटली इस परियोजना के साथ जुड़ा है। चीन ने दुनिया को यह समझाने में कामयाबी हासिल की है कि आर्थिक भूमंडलीकरण के अगले चरण के लिए बुनियादी ढांचा विकास और कनेक्टिविटी की तत्काल सख्त जरूरत है। अन्य प्रमुख शक्तियों को भी इस बात के लिए बाध्य किया गया है कि अपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए वे चीन की शरण में आएं। दुनिया भर में इस मोर्चे पर बहुत बड़ी मांग पैदा हो गई है और चीन इस मांग को पूरा करने की कोशिश में समर्थ दिखने वाले प्रमुख देश के रूप में उभरा है। बहरहाल इस राह में आने वाली बाधाओं से पार पाने में बीजिंग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसमें उसका रवैया और छवि भी आड़े आ रही है। भारत अपनी संप्रभुता के आधार पर चीन की बीआरआइ परियोजना का विरोध तो कर ही रहा है, इसके साथ ही वह परियोजना को लेकर वित्तीय और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी उठा रहा है। ये मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। कई ऐसे देश जो शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ बीआरआइ परियोजना के साथ जुड़े उनमें से कुछ का रुख-रवैया अब बदला हुआ है और वे भारत के सुर में सुर मिला रहे हैं।

अवधेश राजपूत

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने हाल में चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर कर्ज के जाल में फंसने की आशंका जताई। मालदीव और श्रीलंका से लेकर मलेशिया और थाईलैंड तक तमाम देशों में चीन की कई परियोजनाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि चीन की आर्थिक उद्दंडता पर पश्चिमी जगत भी सख्ती कर ही रहा है। जर्मन उद्योग परिसंघ ने हाल में यूरोपीय संघ से कहा है कि चीन के साथ वह सख्त शर्तों पर समझौता करे जो बाजार में उत्पाद डंप करके, आक्रामक तकनीक और वित्तीय बैंकिंग में असमानता जैसे संदिग्ध तौर-तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर भारत ने कई तरह से वैश्विक विमर्श को दिशा दी है। इसमें चीनी बीआरआइ के शोषणकारी स्वरूप को भी उकेरा है। अपनी संप्रभुता के मुद्दे पर बीआरआइ के विरोध से परे भी भारत इस मुद्दे पर सकारात्मक विमर्श पेश करने में सफल रहा है। इस कवायद में भारत को खुद अपनी क्षमताओं से साक्षात्कार करना पड़ा है कि वह स्वयं कैसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मोर्चे पर योगदान दे सकता है। अन्य देशों के साथ साझेदारी को लेकर मौलिक चिंतन के साथ ही उसे स्वयं अपना प्रदर्शन सुधारने पर मजबूर होना पड़ा है। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर भारतीय दृष्टिकोण में नए किस्म की वह गंभीरता देखने को मिली जिसका पहले अभाव नजर आता था। बीआरआइ के विरोध के साथ ही भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त परियोजनाओं से भी समान दूरी बनाकर इस मोर्चे पर संतुलन बिठाया है। इसके बजाय भारत द्विपक्षीय साझेदारियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए दक्षिण एशिया में वह जापान के साथ काम कर रहा है। भारत एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं वाले मॉडल को तरजीह दे रहा है।

बीआआइ को लेकर शुरुआती विरोध के बावजूद भारत इससे जुड़े मुद्दों पर वैश्विक विमर्श को दिशा दे रहा है। भविष्य में यह भारतीय नीति निर्माताओं पर निर्भर करेगा कि वे चीनी परियोजनाओं पर उठते संदेह के बादलों के चलते बनने वाले अवसरों को किस तरह भुनाते हैं ताकि भारत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराने वाले बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर सके।

(लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

चुनाव आयोग के समक्ष बंगाल की बाधा

आशुतोष झा

साफ-सुथरे चुनाव कराने में आ रही समस्याओं के चलते आयोग के समक्ष खुद को साबित करने की चुनौती आ खड़ी हुई है

अब जबकि आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है तो यह कहा जा सकता है कि वर्तमान लोकसभा चुनाव हाल के इतिहास में शायद सबसे तीखे चुनाव साबित होने जा रहे हैं। आम चुनावों का नतीजा कई दलों का अस्तित्व तय करेगा और कईयों की दिशा, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि चुनाव प्रक्रिया विवादों से कब बाहर निकलेगी? स्वतंत्रता के बाद 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है और आज एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा हो रही है वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल एवं नेता जांची-परखी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। क्या इस सबकी इजाजत दी जानी चाहिए? ईवीएम पर हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर विधानसभा में एक के बजाय पांच बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए ताकि किसी को कोई संशय न रहे कि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। इसके कारण इस बार नतीजे आने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन भरोसा पैदा करने के लिए यह जरूरी है। मुश्किल यह है कि इस पर भी कुछ विपक्षी दल सहमत नहीं। कुछ तो ईवीएम को बदनाम करने में जुटे हैं। वे ऐसे आरोप तो लगाते हैं कि कोई भी बटन दबाओ, वोट भाजपा को जाता है, लेकिन इसके पक्ष में सुबूत देने से इन्कार करते हैं। कहना कठिन है कि चुनाव आयोग ईवीएम को बदनाम करने के अभियान से कैसे निपटेगा? वैसे उसके सामने एक अन्य चुनौती आचार संहिता के उल्लंघन की भी है। यह चुनौती सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है।

अभी हाल में चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल में नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक ने कहा कि बंगाल दस पंद्रह साल पहले वाले बिहार की याद दिलाता है। इसका मतलब है कि वहां मतदाताओं को डराने-धमकाने और फर्जी वोट डालने-डलवाने का काम होता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह बयान पसंद नहीं आया और उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि नायक को हटाया जाए। उनकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन क्या वह यह बता सकती हैं कि नायक ने जो कुछ कहा उसमें क्या गलत था? क्या यह सच नहीं है कि आज के दिन पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां वोटर तो दूर, चुनाव कर्मचारी भी डरे हुए हैं। क्या किसी राज्य सरकार के लिए यह शर्म की बात नहीं कि चुनाव कर्मचारी प्रदर्शन कर कहें कि जब तक केंद्रीय सुरक्षाबल नहीं दिए जाएंगे वे चुनावी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे? बंगाल में ऐसी मांग कई स्थानों पर की गई। ये चुनाव अधिकारी और कर्मचारी स्थानीय निवासी हैं, फिर भी उन्हें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं। क्या यह संदेह अतार्किक है कि स्थानीय पुलिस बल और नौकरशाही सत्ता के सामने बेबस है? डेढ़ दो महीने पहले कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के मामले में जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। समझना कठिन है कि प्रदेश सरकार ने सारधा और रोजवैली चिटफंड घोटाले की जांच में छेड़छाड़ के आरोपी राजीव कुमार के साथ खड़े होना जरूरी क्यों समझा? उन्हें सीबीआइ की पूछताछ से बचाने की कोशिश में मुख्यमंत्री तक ने तीन दिन तक धरना दिया। बंगाल में केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि वे बूथ के अंदर घुस रहे हैं और भाजपा को वोट देने के लिए दबाव बना रहे हैं। इन आरोपों पर यकीन करना कठिन है, क्योंकि वहां से खबरें तो यही आ रही हैं कि तृणमूल कार्यकर्ताओं की मनमानी से अन्य दलों के कार्यकर्ता और समर्थक त्रस्त हैं। कहीं-कहीं तो विरोधी दलों के प्रत्याशी भी परेशान हैं।

पश्चिम बंगाल में मत फीसद भी कुछ कहता है। वहां 75 से 82 फीसद तक मतदान होता आ रहा है। एक तरफ अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए चुनाव कर्मी और दूसरी ओर भारी मतदान। क्या यह विरोधाभासी नहीं है? सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता लोगों को ऐसी सीधी धमकी दे रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो सरकार की ओर से मिल रही सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। याद रहे कि लोकसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और अगर वहां चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता स्थापित नहीं हुई तो परिणाम खतरनाक होगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। आजादी के पहले सबसे अधिक जागरूक रहने वाले बंगाल का यह दुर्भाग्य है कि वहां दशकों से यही हो रहा है। एक तरह से यह राजनीतिक विरासत के रूप में सत्ताधारी दल को मिलता आ रहा है। पहले जो काम वामपंथी दल करते थे वही अब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश का बड़ा युवा वर्ग भी राजनीति को एक रोजगार की तरह देखने लगा है। वह चुनाव को रोजी-रोटी का साधन मान बैठा है। बंगाल में जिसे 'क्लब कल्चर' कहते हैं वही राजनीति का हथियार बनता जा रहा है। एक आंदोलन की शक्ल में आईं ममता बनर्जी अगर इस राजनीतिक संस्कृति को खत्म करने के कदम उठातीं तो उनका कद बढ़ता, लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। सभी को याद होगा कि पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों के खिलाफ किस तरह लगभग एक तिहाई सीटों पर कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं उतरा। जहां उतरा वहां मतपेटियां लूट ली गईं या फिर तालाबों में फेंक दी गईं। क्या इसी वजह से यह मांग होती है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलट पेपर से कराए जाएं? आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरों का प्रसार भी बाधित होता है।

बंगाल जैसी स्थिति केरल की भी है। इन दोनों राज्यों से राजनीतिक दलों की मनमानी और राजनीतिक हिंसा की खबरें मुश्किल से ही सुर्खियां बनती हैं। पश्चिम बंगाल में साफ-सुथरे चुनाव कराने में आ रही बाधा के चलते चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। क्या उसके लिए यह रोना रोना उचित है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है? क्या चुनाव में निष्पक्षता और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उसे आलोचना के भय से मुक्त होकर काम नहीं करना चाहिए? आखिर ऐसा क्यों है कि 70 साल के चुनाव आयोग के इतिहास में आज भी टीएन शेषन, लिंगदोह और उनके प्रतिनिधि केजे राव के बाद कोई नाम लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ पाया है? टीएन शेषन और लिंगदोह के पास भी उतनी ही शक्ति थी जितनी आज के चुनाव आयुक्त के पास है, लेकिन उनकी वैसी धमक नहीं दिख रही है जैसी दिखनी चाहिए। ऐसा क्यों है, इस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए।

(लेखक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

क्रोध

क्रोध एक मनोभाव है और यह लगभग हर व्यक्ति को आता है, लेकिन जब यह हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है तो यह विनाशकारी हो जाता है और तब यह हमारे जीवन को हर तरह से प्रभावित करता है। एक निश्चित मात्रा में क्रोध करना मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि क्रोध को दर्शाने का सबसे स्वस्थ तरीका यही है कि आक्रामक हुए बिना अपने क्रोध के भाव को दृढ़तापूर्वक अभिव्यक्त करना। इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने व्यवहार में संयम बरतें। आप क्रोध दिलाने वाले कारणों से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन क्रोध आने पर आप अपनी उग्र प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण जरूर कर सकते हैं।

क्रोध में व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता है और वह अपना होश खो बैठता है। वह मुंह से कुछ भी कह देता है, किसी की हत्या कर सकता है, वह आत्महत्या तक कर सकता है। शास्त्रों में क्रोध की तुलना अग्नि से की गई है। यानी अग्नि का कार्य जलाने-राख करने का है, वैसे ही क्रोध मनुष्य को जला देता है। क्रोध पर नियंत्रण पाने का उपाय बताते हुए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आपको क्रोध आए तो उस व्यक्ति को धन्यवाद दें, जिसकी वजह से आपको क्रोध आया, क्योंकि उसने आप पर कृपा की कि उसने आपको आत्म-निरीक्षण का मौका दिया। वे कहते हैं कि उस व्यक्ति को यह कहकर आप वहां से चले जाइए कि मित्र धन्यवाद, अपने क्रोध पर ध्यान केंद्रित करके मैं कुछ समय बाद लौटता हूं। इसके बाद आप अपने को एक कमरे में बंद कर लें। आपको भयंकर क्रोध आ रहा है तो उसे आने दें। आपके हाथ-पैर-छाती तन रही है तो इन्हें तन जाने दें। आपके हाथ दीवार पर घूंसा मार रहे हैं तो उन्हें मारने दें। इस बीच जो हो रहा है, उसे रोकें नहीं, बल्कि प्रकट होने दें। आप अपने पागलपन को पूरी तरह प्रकट हो जाने दें और तब आप अपनी उस स्थिति को जानने की कोशिश करें। जब आप अपनी इस पागलपन की स्थिति को जानेंगे तो आप भीतर तक हिल जाएंगे कि यह है क्रोध।

भगवन श्रीकृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है।

आचार्य अनिल वत्स

कुष्ठ रोग और भारत

जैन

भारत में कुष्ठ रोग का उन्मूलन न होने के पीछे की एक मुख्य वजह कुष्ठ रोग के प्रति लोगों की सोच भी है

वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के विश्व के 60 फीसद कुष्ठ रोगी भारत ां पर यह प्रति हजार लोगों में से एक से ोगों को अपनी जद में ले रहा है, जबकि ाओ के लक्ष्य के अनुसार कुष्ठ रोग के ी दर 10000 लोगों पर एक मामले से भी कम होनी चाहिए। भारत में जिस तरह कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वह वास्तव में चिंतनीय है। भारत में 1955 में सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया। उसके बाद 31 दिसंबर, 2005 को देश को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया।

कुष्ठ रोग सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है। यह एक ऐसा रोग है, जिसमें शरीर के अंगों का आकार बिगड़ने लगता है। यह एक धीमी गति से बढ़ने वाले एक जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के संपर्क में आने के बाद इसके लक्षण दिखने में कई साल लग जाते हैं। वैसे कुष्ठ रोग का प्रभाव सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं पड़ता, इसका एक व्यापक सामाजिक प्रभाव भी है। अमूमन लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को घृणित या बेहद दयनीय दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों को अमूमन अपनी जीविका कमाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। देश के विभिन्न स्थानों पर तो इन्हें इनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। चूंकि लोग इसे छुआछूत की बीमारी समझते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को परिवार एवं समुदाय से भी अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। कई बार तो देखने में आता है कि लोग कुष्ठ रोग से जुड़े कलंक और गलत अवधारणाओं के कारण इसके लक्षणों को जाहिर नहीं करते और न ही इसका इलाज करवाते हैं। जिसके कारण स्थिति काफी हद तक बिगड़ जाती है। कुष्ठ रोग के इलाज में देरी के चलते व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग हो सकता है, बल्कि कुछ मामलों में इससे तंत्रिकाएं भी स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। देखा जाए तो भारत में कुष्ठ रोग का उन्मूलन न होने के पीछे की एक मुख्य वजह कुष्ठ रोग के प्रति लोगों की सोच भी है। गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने भी कुष्ठ रोग के मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ भेदभाव खत्म करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, अदालत ने कुष्ठ रोग के इलाज को लेकर सरकार को बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा था।

ऐसा नहीं है कि कुष्ठ रोग का पूरी तरह निदान संभव नहीं है। वर्ष 1995 में डब्ल्यूएचओ ने सभी प्रकार के कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए एक मल्टीड्रग थेरेपी विकसित की थी, जो आज पूरे विश्व में मुफ्त उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत में ही कुष्ठ रोग के निदान के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित किया जा चुका है, लेकिन आज भी सबसे अधिक कुष्ठ रोगी भारत में ही हैं। यह आंकड़ा साफतौर पर जाहिर करता है कि महज दवाई विकसित कर लेने से मर्ज का इलाज नहीं होने वाला। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले लोगों के मन में कुष्ठ रोग के प्रति विकसित भ्रांतियों का इलाज किया जाए और यह केवल जागरूकता द्वारा ही संभव है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

जनता भी समझे अपनी जिम्मेदारी

चलन से बाहर बुनियादी मुद्दे शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. बृजेश ने लोकतंत्र के महापर्व में राजनीतिक दलों पर यह आरोप लगाया है कि वे देश और आमजन के आधार से जुड़े मुद्दों से ज्यादा धर्म, संप्रदाय और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इसमें दोष इन पार्टियों का नहीं है, क्योंकि जब हम नागरिक ही सरकारों से मुफ्तखोरी, मात्र अपने धर्म-जाति के लिए ही अच्छे दिनों की उम्मीद रखते हुए अपने कीमती मत का प्रयोग करेंगे तो यही होगा। अमेरिका जैसे देशों का विकास की राह में आगे रहने का मुख्य कारण है कि वहां लोग जाति-धर्म की भावनाओं में बहककर अपने कीमती मत का प्रयोग नहीं करते। वहां चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाते हैं। अगर मतदाता राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की अनदेखी करके अपने कीमती मत का प्रयोग जाति-मजहब की भावनाओं में बहककर करेगा तो संसद में सही लोग चुनकर नहीं जाएंगे। हमारे देश के नेता यह समझ गए हैं कि मतदाताओं को जाति-धर्म की भावनाओं में आसानी से बहकाकर अपना वोट बैंक बढ़ाया जा सकता है। जब तक देश का मतदाता धर्म, जाति और मुफ्त की भावनाओं में बहकता रहेगा, तब तक न तो देश में धर्म-जाति के नाम पर राजनीति करने वाले कम होंगे, न देश के अच्छे दिन आएंगे। देश के बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे लोग मतदाताओं में जागरूकता पैदा करें।

raju09023693142@yahoo.com

टिकट बेचने का आरोप

में एक कांग्रेसी नेता ने एक दूसरी पार्टी के प्रमुख पर करोड़ों रुपये लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। सवाल यह है कि क्या सच में राजनीतिक दल करोड़ों रुपयों के बदले में टिकट का सौदा करते हैं? यदि इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये हमारे देश के लिए अत्यंत घातक है। जो दल पैसों के बदले में टिकट देने की सोच रखते हैं, क्या उनके हाथों में देश सुरक्षित रह सकेगा? दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति करोड़ों रुपये देकर चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतने के बाद उसका सारा ध्यान तो किसी भी तरीके से अपनी तिजोरी भरने में रहेगा। ऐसे में वो देश या समाज का कुछ भी भला नहीं कर सकता। हमें ऐसे नेताओं की पहचान कर उन्हें रोकना चाहिए।

बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद

श्रीलंका में आतंक

अनंतकाल से दो विपरीत विचारधाराओं की लड़ाई होती चली आई है। हर समय में मानवों में धर्म और अधर्म का युद्ध होता चला आया है जो आज भी जारी है और लगता है अनंतकाल तक चलता रहेगा। आतंकवाद से सारी दुनिया परेशान है। हम उससे जूझ ही रहे हैं। अब श्रीलंका में धर्मस्थल पर प्रार्थना करने वालों और होटल में आराम करने वालों पर आतंकियों ने हमला कर तीन सौ से ज्यादा लोगों को मार दिया और पांच सौ से ज्यादा निर्दोषों को घायल कर दिया। कितनी दुखद घटना है, इसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए उतनी कम होगी।

mahesh_nenava@yahoo.com

बदल रहे चुनावी मुद्दे

आम चुनाव में अब विकास के मुद्दे गायब से होते जा रहे हैं। चुनाव के आरंभ में जो मुद्दे उठे थे वे अब किनारे हो गए हैं और नए-नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार विभिन्न नेता चुनाव आयोग एवं ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, उससे नहीं लग रहा कि मौजूदा प्रत्याशियों को समाज की कोई चिंता है। अभी चुनाव के दो चरण ही हुए हैं कि ईवीएम गड़बड़ी की बातें की जाने लगी हैं।

shubhamgupta.s121@gmail.com

राजनीति का गिरता स्तर

देश में राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में मशगूल हैं। चुनाव में अनेक नेता विरोधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो चिंता का विषय। ऐसे लोगों पर चुनाव आयोग कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी गलत टिप्पणी करने से नेता बचें। गलत बयानबाजी से चुनाव प्रभावित होने की संभावना रहती है।

urahuly88@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: न ... काशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -f
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 ... संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। ह